(upto Sept. '88) is 41964 tonnes, valued at Rs. 276.92 crores, as against the target of 104500 tonnes, valued at Bs. 580 crores for 1988-89.

(d) and (e) The major bottleneck' in achieving higher export performance is the lack of sufficient raw shrimp and other fish. The steps being taken by Government in this regard include promotion of shrimp farming for augmenting production of cultured shrimps, setting up of shrmp hatcha-ries and seed banks and promotion of value-added items like IQF (individually Quick Frozen) Shrimps, subsid assistance to exporters/sea food pro-censing industry augmenting the fish-ing fleet, and efforts to reduce duty on import of machinery/prawn feed used by the sea food industry.

**दिल्ली में मकानों की मरम्मत/निर्माण के लिए बैंक ऋण**

893. **श्री सुनील कुमार पटनायक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंक उन लोगों को मकान की मरम्मत/निर्माण के लिए ऋण नहीं देते, जिनके पास अपने मकान के सम्बन्ध में अपने नाम पर न्यायालय का मुख्तियार नामा है जबकि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के 80 प्रतिशत निवासियों के पास ऐसा मुख्तियार नामा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में उन लोगों को ऋण देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, जिनके पास उनके नाम पर अपने मकान का मुख्तियारनामा है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "नहीं" हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्ड फेलेरियो) :** (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गृह-निर्माण कार्यों का वित्तपोषण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन किया जाता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता, प्रतिभूति, प्रमात्रा, मार्जिन, ब्याज की दर, अदायगी की अवधि आदि शामिल हैं। चूंकि ऐसे ऋणों के लिए मुख्य प्रतिभूति संपत्ति का बंधक किया जाना है इसलिये बंधक की जाने वाली सम्पत्ति के बारे में जब तक निर्बाध बिक्री योग्य हक नहीं मिलता है बैंक ऋणकर्ताओं के पक्ष में मुख्तियारनामे के आधार पर वित्त-पोषण नहीं करते हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने, हाल ही में, गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कुछ रियायतों की घोषणा की है जिनके अन्तर्गत, यदि मार्जिन अथवा सरकारी गारन्टी उपलब्ध नहीं है तो बैंक स्व-विवेक से जीवन बीमा पालिसियों, सहकारी बचत-पत्रों, शेयरों तथा डिबेन्चरों, स्वर्ण आभूषणों, अथवा इस प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों को जिन्हें वे उचित समझते हों, स्वीकार कर सकते हैं।

**लम्बे रेशे वाली तथा छोटे रेशे वाली कपास के उत्पादन का लक्ष्य**

894. **श्री मीर्जा इशादबेग :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष लम्बे रेशे वाली तथा छोटे रेशे वाली कपास के उत्पादन का राज्यवार लक्ष्य कितना-कितना है ;

(ख) भारतीय कपास निगम द्वारा राज्यवार कितने खरीद केन्द्र खोले गए हैं और यदि अभी तक ये केन्द्र नहीं खोले गये हैं, तो ये कब तक खोले जाएंगे; और

(ग) कपास के आयात-निर्यात के संबंध में विभिन्न कपास उत्पादक संघों और कपड़ा मिलों के संगठनों ने क्या-क्या मांगें रखी हैं और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम):** (क) सरकार

ने लम्बे स्टेपल तथा छोटे स्टेपल रुई के उत्पादन के लिए कोई निश्चित राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं ।

(ख) चालू रुई वर्ष 1988-89 के दौरान भारतीय कपास निगम का निम्नलिखित रूप में विभिन्न राज्यों में 240 खरीद केन्द्र चलाने का प्रस्ताव है :

| राज्य | केन्द्रों की संख्या |
|---|---|
| पंजाब . . . | 20 |
| हरियाणा . . . | 15 |
| राजस्थान . . . | 25 |
| मध्य प्रदेश . . . | 40 |
| गुजरात . . . | 65 |
| आन्ध्र प्रदेश . . . | 45 |
| कर्नाटक . . . | 20 |
| तमिलनाडु . . | 10 |
| **योग :** | 240 |

इस समय कपास की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तरों से अधिक हैं । जब कभी भी बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमतों के स्तर पर पहुंचती हैं, निगम इन केन्द्रों का संचालन करना प्रारंभ कर देगा ।

(ग) एक ओर उपजकर्ता निकाय तो निर्यात कोटा की रिलीज के लिए अभिवेदन दे रहे हैं किंतु दूसरी ओर मिलों के संगठन रुई निर्यात के विरुद्ध प्रतिवेदन दे रहे हैं । अब तक कपास के निर्यात के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

**मुद्रास्फीति के संबंध में विश्व बैंक की चेतावनी**

895. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने गत वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार को चेतावनी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) देश में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को देखते हुए विश्व बैंक द्वारा क्या आशंकाएं व्यक्त की गयी थीं और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ।

**वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) :**

(क) से (ग) वर्ष 1988 के लिए विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कृषि मूल्यों पर सूखे का प्रभाव पड़ने के कारण, भारत में 1980 के दशक के प्रारंभ से पहली बार मुद्रास्फीति लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच गई ।

रिपोर्ट में सूखे के कुप्रभावों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय पर की गई कार्यवाही और इस प्रकार की आपात स्थितियों का सामना करने के लिए सुस्थापित संस्थापन तंत्र की मौजूदगी के लिए भारत की सराहना की गई है । केन्द्रीय सरकार ने, अपने खाद्यान्न भंडार से खाद्यान्न जारी करके और खाद्यतेलों, दालों और चारे का आयात करके मूल खाद्यान्नों की उपलब्धता को बनाए रखा है और कीमतों में वृद्धि को नियंत्रण में रखा है ।

**Decline in the export of engineering goods**

896. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the comparative percentage of decline in the export of engineering goods as against the target in 1988 (till date) as compared to the' same period during 1987;

(b) what are the names of the countries where the export of engineering goods have shown a decline stating the reasons therefor; and